of India should not have exercised control over the utilisation of grant. It may be a grant but it is still money. This grant may have been utilised for some other purpose.

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: Let me first correct the impression of the hon. Member. I do not know if my hon. Minister of State used the word 'no other option'. If he did, he obviously meant there may have been other options but this was an outright grant. We were not spending any money at all except the 5 million pounds that we were going to spend on some spares. Apart from that, we are not spending any money. I think, in that context, what the Minister meant when he used the words 'no option' was not that other alternatives were not available to us, but then the outflow would have been much later. As far as what the hon. Member asked about the alleged reckless use of the grant is concerned, there were two committees which went into this and did clear it on technical parameters and also the economic parameters. Whatever the differentiation there was on the economic parameters of operation, that was compensated by the 10 million pounds that was given again as an outright grant against operational loss. Therefore, there were two Committees which had cleared this helicopter subsequently.

श्री मोहम्मद सलीम : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जैसा अपने उत्तर में बताया कि यह हमें बाहर से अनुदान के तौर पर मिला था। लेकिन यह भी पवन हंस के लिए लायबिलिटीज बना है। जो फोरेन एक्सचेंज दिया गया था वैस्टलैंड खरीदने के लिए उसके लिए पवन हंस को काफी इक्विवेलेंट डिपोजिट करना पड़ा गवर्नमेंट के एकाउंट में और वह पूरा नहीं कर पाये, उसके लिए ब्याज भरना पड़ रहा है जिसके कारण पवन हंस खुद-ब-खुद सूखा जा रहा है, मरा जा रहा है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि उन्होंने पार्लियामेंट के जवाब में यह कहा है कि—

"The foreign exchange cost of acquisition of 21 helicopters, spare engines, ground support equipment and engine test bed was 70 million pounds equivalent to Rs. 141.53 crores."

जो ओरिजिनल कान्ट्रेक्ट था उसके मुताबिक इनीशियल रेंज ऑफ स्पेयर्स तमाम के साथ दिये, लेकिन उस वक्त जो एंटीसिपेट किया गया था स्पेयर्स के लिए उसके बावजूद बाद में यह देखा गया कि यह स्पेयर्स काफी नहीं है। इतनी टैक्नीकल स्नेग्स हो रही है और ग्राउंडिंग करना पड़ रहा है, तो बाद में और भी स्पेयर्स खरीदने पड़े। उसके लिए जो फारेन एक्सचेंज एमाउंट खर्च करना पड़ा वह कितना था और किस के अनुपात से मिला था और वह सिर्फ जो प्राइम सप्लायर्स हैं, मैन्यूफैक्चरर्स हैं उनसे खरीदा गया या बीच में मिडिलमैन थे तो वह कौन मिडिलमैन थे?

श्री माधव राव सिंधिया : सर, ब्याज का तो सवाल ही नहीं उठता। अभी आउट राइट गारंटी था तो ब्याज का तो सवाल ही नहीं उठता; जो पूरा एमाउंट आया 65 मिलियन पौंड का और 10 मिलियन पौंड आपरेशनल लोस के एगेंस्ट, वह तो आउट राइट गारंटी था, उस पर कोई ब्याज तो था नहीं। जहां तक स्पेयर्स का सवाल है, आनरेबिल मेंबर कलमाडी साहब ने भी यह बात पूछी थी, उसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स जो भी अभी तक आउट फ्लो हुआ है, हर एक डिटेल्स मैं मेम्बर्स को देने के लिए तैयार हूं अगर वह चाहते हैं।

Coal supply to power plants in Madhya Pradesh

*3. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State of Madhya Pradesh is not be-

ing supplied the requisite quantity of coal for its power plants and for domestic and industrial consumption by the concerned coal mines;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) what action Government propose to take to augment the coal supply to the State of Madhya Pradesh?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDAR): (a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) There has been some shortfall in supply of coal to industrial and domestic consumers because more coal had to be made available to higher priority core sectors like power, cement, steel and railways. As regards supply of coal during last four months, to six Thermal power stations located in Madhya Pradesh, the details are given in Annexure. (*See* below)

(c) All out efforts are being made to increase supply of coal to core sector. As regards non-core sector, Ministry of Coal has issued instructions to coal companies to supply at least 50 per cent of the linked quantity of coal to them by rail or by road. These measures are expected to augment supply of coal to all consumers including the consumers in the State of Madhya Pradesh.

Annexure

SLC Linkage, Receipts consumption and closing stock of coal at the Thermal Power Stations in Madhya Pradesh for the month of April to July, 1991.

(Fig. in '000 tonnes)

Sl. No.	Name of T.P.S.	Particulars	April, 1991	May, 1991	June, 1991	July, 1991
1	2	3	4	5	6	7
1.	Amarkantak	Linkage	120	120	120	120
		Receipts	102	77	47	66
		Consumption	79	85	62	47
		Stocks (Days)	75(19)	68(17)	53(13)	69(17)
2.	Korba East	Linkage	210	210	210	180
		Receipts	149	117	159	118
		Consumption	155	115	157	117
		Stocks (Days)	101(14)	106(15)	98(14)	107(18)
3.	Korba West	Linkage	330	330	330	330
		Receipts	267	278	285	227
		Consumption	313	264	249	296
		Stocks (Days)	73(7)	89(8)	138(13)	68(6)

1	2	3	4	5	6	7
4.	Satpur	Linkage	400	400	400	350
		Receipts	289	279	295	328
		Consumption	311	302	272	300
		Stocks(Days)	9(1)	2(Nil)	24(2)	40(3)
5.	Korba STPS(NTPC)	Linkage	750	750	750	750
		Receipts	741	702	688	750
		Consumption	781	739	692	761
		Stocks (Days)	127(5)	106(4)	112(4)	88(4)
6.	Vindhyachal (NTPC)	Linkage	390	390	390	390
		Receipts	281	163	241	263
		Consumption	316	282	247	287
		Stocks (Days)	120(9)	96(7)	96(7)	70(5)

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश को कोल वेगंस का जो कोटा है वह राज्य की आवश्यकता की देखते हुए बहुत कम है और पर्याप्त मात्रा में कोयला मध्य प्रदेश को उपलब्ध न होने की वजह से मध्य प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । साथ ही वहां के उपभोक्ता भी बहुत परेशान हैं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि प्रदेश को वास्तव में कितना कोयला आबंटित किया गया कितना कोयला ढुलाई किया गया, वास्तविक मांग, आबंटन तथा ढुलाई का प्रतिशत पिछले तीन वर्षों में क्या है ? "ख" पार्ट—मध्य प्रदेश को पूर्ण कोटा होने के लिए कितने वैगंस की आवश्यकता है तथा अभी तक कितने वेगंस आबंटित किए गए हैं ? इसका तीसरा भाग है—क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत पुरानी माइंस हैं, इसलिए क्या मध्य प्रदेश में कोयला आपूर्ति को वृद्धि करने के लिए डब्ल्य० सी०एल० के अंतर्गत कभी माइन्स खोली जायेंगी ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर खोली जायेंगी और उनमें कितना प्रोडक्शन मिलेगा, क्योंकि हाल ही में महाकोशल रीजन में डीलिंग हुई है, उसके क्या परिणाम निकले हैं, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ।?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI P. A. SANGMA): Sir, as far as the availability of wagons is concerned, there is an overall shortage, in the whole of the country. It is not confined to the State of Madhya Pradesh only. We are trying to improve the availability. We are in constant touch with the Railways.

In regard to the allotment, we do not allot it in terms of States. It is done only in terms of sectors like power, cement, steel and other consumers. Unfortunately, I do not have that figure with me. All these figures have to be added up. I can furnish the information to the hon. Member later on.

As far as the question of new projects for Madhya Pradesh is concerned, we are going to take up about

41 ne wprojects during the Eighth Five-Year Plan. We are going to take up 41 new projects with a capacity of 25-20 million tonnes and the investment will be approximately Rs. 2,000 crores.

श्री सुरेश पचौरी : मान्यवर, सरकार ने गल्फ वार के समय यह निर्णय लिया था कि स्माल कंज्यूमर्स को कोयला प्रदान किया जाएगा । अभी सरकार ने अपने उत्तर में स्वीकारा है कि घरेलू उपभोक्ताओं को कोयला आपूर्ति में कमी रही । इसलिए मेरा ऐसा सुझाव है कि इसे दूर करने के लिए यह जरूरी है कि स्टाक यार्ड नए बनाए जायें और जो अभी एंगजीस्टिंग स्टाक यार्ड हैं उनको ज्यादा कोयला प्रदान किया जाए । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर स्टाक यार्ड खोलने का प्रस्ताव है ताकि कंज्यूमर्स को कोयला उपलब्ध कराया जा सके ।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर स्टाक यार्डस खोलने का प्रस्ताव है ताकि कंज्यूमर्स को कोयला उपलब्ध कराया जा सके ? साथ ही मध्य प्रदेश में जो पावर स्टेशंस हैं उनमें कोयले की जितनी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के विपरीत जितना कोयला अभी तक प्रदान किया गया है वह बहुत कम है जैसा कि आपने अपने चार्ट में प्रदर्शित किया है । क्या उस कमी को दूर करने के लिए आपकी तरफ से प्रयास किए जायेंगे ? साथ ही क्या रेलवे विभाग की तरफ से आपको सहयोग प्रदान किया जा रहा है ? मध्य प्रदेश में वैगंस बढ़ाने के लिए क्या मध्य प्रदेश सरकार ने और कोयला विभाग ने रेलवे को कोई अनुशंसा की है और रेल विभाग का इस संबंध में क्या रिस्पांस है ? मैं इन बातों की जानकारी मंत्री महोदय से चाहता हूं ।

SHRI P. A. SANGMA: Sir, there are 50 stockyards existing all over the country out of which 4 are in Madhya Pradesh. We realise the need of opening new stockyards in order to make coal available to the consumers—particularly domestic consumers. We have plans to open new stockyards but railways have expressed their difficulties of moving call to the stockyards. We are trying to negotiate with them. We are going to open about 20 new stockyards out of which 2 will be in Madhya Pradesh (*Interruptions*). I think within six months' time we should be able to finalise that.

As far as power sector is concernend, Madhya Pradesh has got six thermal power stations. Out of these six power stations the problem is confined to one particular power house, which is Satpura power station. (*Interruptions*). More acute problem is in Satpura power station, the reason being that when this power station was sanctioned there was the presumption that there will be enough coal available in that area. But unfortunately, we find now that the availability of coal is not to the extent it is required for the power project. The requirement is 4 million tonnes and at the moment we are producing only 2.6 million tonnes. Therefore, there is need to open new mines in the neighbouring places. We are at it. One project at Chhatarpur has already been sanctioned. We are going to sanction one more project at Tawa. So, there will be two more projects, one at Tawa and the other at Chhattarpur.

श्री राघव जी : माननीय सभापति जी मध्य प्रदेश कोयला के उत्पादन में एक प्रमुख प्रदेश है और उसके बावजूद भी न तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योगों को कोयला मिल रहा है और न ही गैर महत्वपूर्ण उद्योगों को कोयला मिल रहा है अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वे गैर महत्वपूर्ण उद्योगों को भी 50 प्रतिशत लिंकड क्वांटिटी कोयला उपलब्ध करायेंगे लेकिन इन्होंने जो चार्ट प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक महत्वपूर्ण उद्योगों को भी किसी-किसी महीने में 50 प्रतिशत कोयला उपलब्ध नहीं कराया गया है । अमरकंटक तापीय विद्युत गृह को जून 1991 में

120 हजार टन कोयले की आवश्यकता थी जब कि उसे केवल 47 हजार टन कोयला उपलब्ध कराया गया है। तो जब महत्वपूर्ण उद्योगों को ही आप पर्याप्त कोयला नहीं दे पा रहे हैं तो गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों को कब से देना शुरू करेंगे? आप ने इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस कब जारी की हैं और वर्तमान में 50 प्रतिशत के स्थान पर कितना कोयला गैर-महत्वपूर्ण उद्योगों को प्रदान किया जा रहा है, यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I have had an occasion to inform this hon. House earlier that the non-core sector was really facing shortage of coal because the policy of the Government was to meet 100 per cent requirement of the core sector. When I reviewed the whole situation it was found that it was not justified, the non-core sector was being denied the coal. Therefore, on 18th of the last month we have taken a decision that 50 per cent of the requirement of the noncore sector must be met immediately. The railways were very kind to provide us with the required number of wagons. Of course, the policy is to supply that coal either by rail or by road. I am aware that 50 per cent is not enough, but I think that will help them to a great extent. In fact, there was a time when I was receiving almost 50 to 100 letters and petitions every day but after having taken this decision of meeting 50 per cent of the requirements of coal—I am happy to inform the House—the number of complaints that I was receiving has been reduced to a great extent. I know it is not enough, but we will try to improve our performance.

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, यह बड़ी विडंबना है कि देश में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला प्रदेश होने के बावजूद मध्य प्रदेश के ही पावर प्लांटस तथा मध्य प्रदेश के ही कारखानों को कोयला नहीं मिल पा रहा है। मैं केवल दो बिन्दुओं पर मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं। एक तो यह कि जो यह विशियस सर्किल है जिसमें कभी कोयला खदान वाले, कभी रेल मंत्रालय वाले, कभी पावर प्लांट वाले एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और उनसे आपस में कोई समन्वय नहीं हो पाता। केवल अधिकारियों के लेवल पर आप समन्वय करने की कोशिश करते हैं। तो क्या परिस्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम उठाएंगे कि राजनीतिक स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर भी इन तीनों एजेंसियों में कोआर्डिनेशन हो, समन्वय हो जिससे परिस्थिति में सुधार आए।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो आपने लिंकेज की नीति बनाई है उसमें जहां कोयला होता है उसके पास के पावर प्लांटस को उस क्षेत्र से कोयला न देकर दूसरे से देते हैं तो क्या कम से कम मध्य प्रदेश जैसे स्टेट के लिए जहां आदिवासी, उजड़ते हैं, जंगल उजड़ते हैं तब कोयला निकलता है, तो वहां के लिए आप लिंकेज की नीति पर कोई आधार भूत, आमूल सुधार लाने की कोशिश करेंगे?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I can assure the House that there is perfect understanding between the various Ministries, both at officers' level and Ministers' level. In fact, myself, the Railway Minister and the Steel Minister have been meeting quite regularly and we are trying to coordinate our functioning.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Make it a formal plan so that the three or four Ministers should sit and coordinate.

SHRI P. A. SANGMA: We are meeting this week again and we will try to formalize it; make it a permanent affair. As far as the movement is concerned, I do agree with the honourable Member that the coal that is being produced in Madhya Pradesh is not made available 100 per cent there. It is not possible because we have to take the national economy in totality and, therefore, we have to move the coal of Madhya

Pradesh to other States also. Our problem has been with the Singareni Collieries. Though it was supposed to meet the requirements of certain regions of the country, unfortunately, Singareni is not working properly and, therefore, in order to meet the requirements of the southern region, we have to divert quite a bit of the quantity of coal from Madhya Pradesh to the southern region.

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय लिंकेज सिस्टम रहने से बहुत आसानी होती है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि लकेज सिस्टम में जिस किसी कोइलरी ने डिफाल्ट किया एक पर्टिकुलर पावर प्लांट को कोयला देने के बारे में उसके बारे में कोई जांच करवाई है या नहीं ? यदि कारवाई है तो जो दोषी हैं उनके ऊपर भी कुछ कार्यवाही करेंगे ?

Have you taken any action against those who have defaulted in giving coal to those particular power projects? Was it not their duty to inform the Ministry or Coal India that this was going to happen? This is my question.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, actually, we have information we monitor it on a day-to-day basis. We have a monitoring system about the requirement of coal, availability of coal, despatches and stock position of every thermal plant and every steel plant every day. But we have problems of movement. Mishraji knows very well that in spite of the fact that coal is available, movement becomes difficult because of many reasons. As I said, we are now trying to coordinate our functioning and we will coordinate it.

श्री नरेश पुगलिया : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कोल को शोर्टेज थ्रू आउट कंटरी में है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इनके बुक-स्टाक में कितने मिलियन टन कोयला अवेलेबल है और उसके बाद कोल की शोर्टेज क्यों है इसकी जांच पार्लियामेंटरी कंसलटेटिव कमेटी को भेज कर करायेंगे ?

SHRI P. A. SANGMA: Sir, I did not say that there is shortage of coal. In fact, coal is available. As of today our stock position is about 35 million tonnes. I am talking about the availability at the consumption point. The non-availability at the consumption point is not because coal is not available but because we have constraints of movement. That is the reason.

Subsidy on Cooking Gas

*4. SHRI SOM PAL:†
SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the element of subsidy per cooking gas cylinder and what is the break up of inputs in gas cylinder; and

(b) whether private enterprises or Municipalities have offered to lay the pipeline for supplying cooking gas to Ahmedabad, Kalal and Mehasana; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS WITH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) Actual subsidy depends on various factors *viz.* costs of production in different units, volume and prices of imported LPG, bottling costs, transportation costs etc. The average subsidy per cylinder during 1991-92 is estimated to be about Rs. 60.00.

(b) Yes, Sir. Gas has not been allocated for supply to these towns since enough gas is not available.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sompal.